तापमान
अधिकतम 41.2 डिग्री
न्यूनतम 26.6 डिग्री

हरिभूमि
महासमुंद भूमि
रायपुर, शनिवार 25 अप्रैल 2026

सरायपाली | बसना | पिथौरा | बागबाहरा | तुमगांव | खरियार रोड

14 सशक्त पंचायत के संकल्प को मजबूत करने पर दिया जोर

14 साल्हेभांठा में पोषण पखवाड़ा के तहत हुए विविध...

खबर संक्षेप

सगाई में मारपीट

महासमुंद। ग्राम मोखापुटका सगाई कार्यक्रम में गए एक युवक के साथ तीन लोगों ने मारपीट कर दी। सरायपाली पुलिस को अर्जुन महानंद पिता अलेख राम महानंद (19 साल) आंवलाचक्का ने बताया कि 22 अप्रैल को वह संतोष चौहान की सगाई कार्यक्रम में ग्राम मोखापुटका के महेत्तर चौहान के यहां गांव के अन्य लोगों के साथ गया था। सगाई कार्यक्रम होने के बाद शाम लगभग 4:30 बजे वह महेत्तर चौहान के घर के सामने खड़ी एक मोटर सायकल में बैठा था, उसी समय ग्राम मोखापुटका का प्रेम चौहान आया और कहा कि मेरी गाड़ी में क्यों बैठा है, इस गाड़ी में बैठने की तुम्हारी औकात नहीं है कहकर गाली गलौज करते हुये हाथ मुक्का से मारपीट करने लगा उसी समय प्रेम चौहान के साथी सफेद एवं नित्या चौहान आए और तीनों ने मिलकर जान से मारने की धमकी देकर हाथ मुक्का से मारपीट किय। मामले की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध धारा 115(2), 296, 3(5), 351(2) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

निरीक्षण : पांडुलिपि सर्वेक्षण की प्रगति का कलेक्टर ने लिया जायजा

गुरुकुल कोसरंगी के पुस्तकालय में संरक्षित दुर्लभ ग्रंथों का अवलोकन

हरिभूमि न्यूज ▶▶| महासमुंद

जिले में पांडुलिपि सर्वेक्षण कार्य एवं ज्ञान

- आर्ष ज्योति गुरुकुल के पुस्कालय पहुंचे कलेक्टर, पांडुलिपियों का किया अवलोकन

भारतम ऐप में अपलोड की प्रगति का जायजा लेने कलेक्टर विनय कुमार लंगेह गुरुकुल कोसरंगी के पुस्तकालय कक्ष पहुंचे।

इस दौरान उन्होंने वहां संरक्षित 44 प्रकार की लगभग 3000 पृष्ठों की पांडुलिपियों का सूक्ष्म अवलोकन किया। पुस्तकालय में भोजपत्र, ताड़पत्र एवं बांस पर संरक्षित रामायण के समस्त कांड, चारों वेद तथा आयुर्वेद से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ सुरक्षित रखे गए हैं, जो क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। कलेक्टर लंगेह ने इस कार्य के लिए संस्था के आचार्यों की सराहना करते हुए कहा कि पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान देश की अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण की दिशा में एक अहम पहल है। यह अभियान हमारी प्राचीन लिपियों एवं ज्ञान को दस्तावेजीकृत कर भावी पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे ज्ञान भारतम ऐप डाउनलोड कर इस अभियान से जुड़ें और सक्रिय भागीदारी निभाएं। उन्होंने कहा कि जिले में यदि कहीं भी 100 वर्ष या उससे अधिक पुरानी पांडुलिपियां उपलब्ध हों, तो इसकी जानकारी अवश्य दें, ताकि उनके संरक्षण की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जा सकें। उन्होंने स्पष्ट किया कि पांडुलिपियों को जमा करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनका फोटो लेकर ऐप में अपलोड करना ही पर्याप्त है।

मोबाइल के माध्यम से प्रक्रिया बेहद सरल

जिला संयोजक एवं डीएमसी रेखराज शर्मा ने जानकारी दी कि मोबाइल के माध्यम से यह प्रक्रिया बेहद सरल है। इसमें मिशन एवं सेटअप, सर्वेक्षण प्रारंभ करना, विवरण दर्ज करना तथा सबमिशन एवं ट्रैकिंग जैसे चार प्रमुख चरण शामिल हैं। उपयोगकर्ता मोबाइल नंबर या ईमेल के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। सटीक स्थान की जानकारी के लिए ऐप को लोकेशन एक्सेस देना आवश्यक होता है। उन्होंने बताया कि सर्वेक्षण के दौरान भाषा का चयन अपनी सुविधा अनुसार किया जा सकता है, हालांकि विवरण अंग्रेजी में दर्ज करना अनिवार्य है ताकि संकलन प्रक्रिया सुगम हो सके। साथ ही संकुल समन्वयकों के माध्यम से भी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है।

ये रहे मौजूद

इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी विजय कुमार लहरे, बीआरसीसी जागेश्वर सिन्हा, गुरुकुल के प्राचार्य आचार्य मुकेश कुमार, सीएसी अशोक साहू, सुरेश कुमार, पंचानन, ओंकार, मुरली आर्य, नंदलाल आर्य सहित अन्य शिक्षक एवं नागरिक उपस्थित रहे।

मंडी उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा कल होगी, 19 परीक्षा केंद्रों में 4917 परीक्षार्थी होंगे शामिल

हरिभूमि न्यूज ▶▶| महासमुंद

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड अंतर्गत उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन रविवार 26 अप्रैल 2026 को महासमुंद जिले में एक पाली में किया जाएगा। परीक्षा का समय प्रातः 10 बजे से 12:15 बजे तक निर्धारित है। जिसमें जिले के 19 निर्धारित परीक्षा केंद्रों में कुल 4917 परीक्षार्थी शामिल होंगे। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने परीक्षार्थियों की सुविधा, सुरक्षा एवं सुचारू परीक्षा संचालन के लिए प्रत्येक परीक्षा केंद्रों के लिए नियुक्त पर्यवेक्षकों एवं केंद्राध्यक्षों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर सचिन भूतड़ा, नोडल अधिकारी सृष्टि चंद्राकर, पर्यवेक्षक एवं केंद्राध्यक्ष मौजूद थे।

कलेक्टर लंगेह ने कहा कि परीक्षा केंद्रों में शांतिपूर्ण एवं नकलविहीन वातावरण सुनिश्चित किया जाए। प्रवेश द्वार पर व्यापम द्वारा जारी निर्देशानुसार कड़ाई से चेकिंग व्यवस्था हो तथा प्रतिबंधित सामग्री बिल्कुल न ले जाने दी जाए। परीक्षार्थियों के प्रवेश, बैठक व्यवस्था एवं प्रश्नपत्र वितरण में समय पालन का विशेष ध्यान रखा जाए। परीक्षा केंद्रों में पेयजल व प्राथमिक उपचार जैसी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध रहें। नकल या अनुचित साधनों के किसी भी प्रयोग पर कड़ी निगरानी के लिए अभ्यर्थियों की फ्रिक्सिंग और वीडियोग्राफी की जाएगी तथा पुलिस पेट्रोलिंग दल भी तैनात रहेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की सूचना पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि परीक्षा प्रक्रिया में पूर्ण गंभीरता, पारदर्शिता और संयम का पालन कर परीक्षा को सफलतापूर्वक कराएं।

कलेक्टर ने अभ्यर्थियों को सलाह देते हुए कहा कि परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पूर्व प्रातः 9:30 बजे बंद कर दिया जाएगा। तत्पश्चात परीक्षार्थियों के लिए प्रवेश निषेध रहेगा। सभी अभ्यर्थी समय का विशेष ध्यान रखते हुए निर्धारित समय से पूर्व परीक्षा केंद्रों में पहुंचना सुनिश्चित करें। जिससे फ्रिस्किंग (सुरक्षा जांच) एवं फोटो युक्त मूल पहचान पत्र से सत्यापन की प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके। व्यापम के निर्देशानुसार परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण और केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने तीन सदस्यीय उड़नदस्ता दल का गठन किया गया है।

खबर संक्षेप

राज्यपाल के निर्देश पर विशेष जांच शिविर

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका ने बलरामपुर जिले के कुसमी विकासखंड अंतर्गत ग्राम धनेशपुर में दिव्यांग बच्चों की अधिक संख्या को गंभीरता से लेते हुए समाज कल्याण विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग को संयुक्त रूप से विशेष जांच शिविर करने के निर्देश दिए हैं। राज्यपाल ने कहा है कि दोनों विभाग आपसी समन्वय से ग्राम धनेशपुर में विशेष शिविर आयोजित करें, जहां दिव्यांग बच्चों की स्वास्थ्य जांच, आवश्यक परीक्षण तथा उनकी स्थिति का आकलन किया जाए। साथ ही दिव्यांगता के संभावित कारणों का पता लगाने के लिए विस्तृत सर्वे एवं चिकित्सकीय अध्ययन भी कराया जाए। निर्देशानुसार समाज कल्याण विभाग और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम गांव पहुंचकर घर-घर सर्वे करेगी तथा पात्र बच्चों और नागरिकों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं दिव्यांग कार्ड बनाने की प्रक्रिया भी सुनिश्चित करेगी। शिविर के माध्यम से जरूरतमंद बच्चों को सहायक उपकरणों का वितरण भी किया जाएगा, ताकि उन्हें दैनिक जीवन, शिक्षा और आवागमन में सुविधा मिल सके। राज्यपाल ने अधिकारियों से कहा है कि प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाए तथा बच्चों के बेहतर उपचार, पुनर्वास और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए ठोस कार्ययोजना बनाई जाए।

सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं : जकांछ

रायपुर। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी के प्रकरण में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को ऐतिहासिक बताया है। पार्टीजनों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा अमित जोगी के विरुद्ध दिए निर्णय पर रोक (स्टे) लगा दी है। यह निर्णय न केवल न्यायपालिका में विश्वास को और मजबूत करता है, बल्कि यह भी सिद्ध करता है कि सत्य को अस्थायी रूप से परेशान किया जा सकता है, परंतु उसे पराजित नहीं किया जा सकता। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने इस न्यायपूर्ण निर्णय के लिए सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया है। पार्टी का मानना है कि यह सत्य और न्याय की विजय है।

रसायन विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए कैंपस प्लेसमेंट

रायपुर। शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज में 23 अप्रैल को रसायन विज्ञान (केमिस्ट्री) के विद्यार्थियों के लिए कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन अलीशान ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा "क्वालिटी इंजीनियर" पद के लिए किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत रसायन विभागाध्यक्ष डॉ. गोवर्धन व्यास के प्रेरणादायक उद्बोधन से हुई। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि इंटरव्यू केवल चयन की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्मविश्वास, तैयारी और व्यक्तित्व की वास्तविक परीक्षा है। कंपनी के प्रतिनिधियों ने विद्यार्थियों को कंपनी की कार्यप्रणाली, अवसरों और जॉब प्रोफाइल के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इंटरव्यू पैनल में एजीएम ज्ञानेंद्र मोहन खरे, अनुसंधान एवं विकास विभाग से डॉ. नागेंद्र बाकू तथा प्लांट एचआर मैनेजरतरुण वर्मा उपस्थित रहे।

सांसद बृजमोहन से नागरिकों ने की मुलाकात

रायपुर। रायपुर में लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल से गुरुवार को 1बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिकों ने मुलाकात की। इस दौरान लोगों ने अपनी विभिन्न समस्याएं और मांगें उनके सामने रखीं। सांसद ने सभी नागरिकों की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और संबंधित मामलों के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। अपने निवास पर हुई इस जनसुनवाई में बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जनता ने उन्हें हमेशा प्यार और विश्वास दिया है, ऐसे में उनके सुख-दुख में साथ खड़े रहना उनका कर्तव्य भी है और सौभाग्य भी।

9 लाख किसानों का फार्मर आईडी नहीं, खाद मिलने में होगी दिक्कत

हरिभूमि न्यूज ▶▶| रायपुर

खाद्य वितरण के लिए फार्मर आईडी की अनिवार्यता से छत्तीसगढ़ के 9 लाख से अधिक किसानों को न सिर्फ यूरिया डीएपी एनपीके और पोटाश जैसी खाद मिलने में दिक्कत होगी, बल्कि विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ और सब्सिडी से भी किसान वंचित होंगे। छत्तीसगढ़ की विभिन्न सहकारी समिति में कुल 40 लाख 89 हजार 908 किसान पंजीकृत हैं। फार्मर आईडी बनाने के लिए एग्री स्टेक परियोजना में अब तक मात्र 31 लाख 68 हजार 555 किसानों का सत्यापन हुआ है, इस प्रकार से लगभग 21 प्रतिशत किसान पंजीयन से वंचित हैं। सरकार छत्तीसगढ़ के इन 9 लाख 21 हजार 353 किसानों को खाद नहीं मिल पाएगी।

खाद वितरण की व्यवस्था को पारदर्शी बनाने शासन ने बड़ा कदम उठाते हुए फार्मर आईडी अनिवार्य कर दी है। जिन किसानों की फॉर्मर आईडी होगी, उन्हें ही समितियों से यूरिया समेत अन्य खाद मिल सकेगी। नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सही किसानों तक सही मात्रा में खाद पहुंचाना है, ताकि अनियमित वितरण और कालाबाजारी को रोका जा सके। यह व्यवस्था 2026-27 के खरीफ सीजन से लागू होगी।

नई व्यवस्था के तहत खाद वितरण होगा डिजिटल सिस्टम से

खाद का वितरण जमीन और फसल के हिसाब से

उल्लेखनीय है कि पिछले खरीफ सीजन के लिए एग्रीस्टेक को अनिवार्य किया गया था, इसी तरह आगामी सीजन के लिए खाद वितरण में फॉर्मर आईडी को अनिवार्य किया गया है। अब यूरिया समेत दूसरी खाद खरीदने के लिए किसानों के पास फार्मर आईडी होना जरूरी है। नई व्यवस्था के तहत खाद वितरण प्रक्रिया को डिजिटल सिस्टम के जरिए पूरा किया जाएगा। इसमें किसान को उसकी जमीन और फसल के आधार पर तय मात्रा में खाद ही दी जाएगी। खाद का वितरण किसान की जमीन और फसल के हिसाब से तय किया जाएगा।

फॉर्मर आईडी बनाने दस्तावेज होंगे जरूरी

किसानों को बैंक ऋण, सब्सिडी और अन्य योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से मिल सकेगा। फॉर्मर आईडी के लिए पंजीयन कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। फॉर्मर आईडी बनाने के लिए आधार कार्ड, जमीन से जुड़े डॉक्यूमेंट, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर जैसे जरूरी दस्तावेज देने होंगे।

रजिस्ट्रेशन नहीं तो खाद और योजनाओं का नहीं मिलेगा लाभ

राज्स सरकार ने इस संबंध में स्पष्ट किया है कि जिन किसानों की फार्मर रजिस्ट्री नहीं होगी, उन्हें न सिर्फ यूरिया और डीएपी मिलने में दिक्कत होगी, बल्कि कई सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाएगा। फॉर्मर आईडी के बिना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों पर सब्सिडी, सहकारी समितियां से खाद वितरण और सरकारी खरीद केंद्रों पर फसल की खरीद का लाभ भी किसान नहीं ले पाएंगे। सभी सुविधाओं के लिए अब फार्मर आईडी जरूरी कर दी गई है।

कहीं टंकी-पाइप लाइन के कार्य अधूरे तो कहीं पूर्ण होने के बाद भी सप्लाई शुरू नहीं

हरिभूमि न्यूज ▶▶| रायपुर

हर घर नल कनेक्शन के माध्यम से जल पहुंचाने का लक्ष्य लेकर जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत रायपुर जिले के 477 ग्रामों में लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग (पीएचई) के माध्यम से कार्य किए जा रहे हैं। इस लक्ष्य के तहत लगभग तीन सौ ग्रामों में कार्य पूर्ण भी हो गए हैं, जहां पानी टंकी, पाइप लाइन बिछाने से लेकर घरों में नल कनेक्शन तक लग चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी इनमें से दर्जनों गांव में पानी की सप्लाई शुरू नहीं हो पाई है। इसकी वजह कहीं बोर सूख चुके हैं, तो कहीं जल स्तर नीचे चला गया है। इसके अलावा लगभग 177 ग्रामों में अभी तक कार्य अधूरे पड़े हुए हैं। इनमें भी कहीं टंकी, कहीं पाइप लाइन एवं कनेक्शन के कार्य नहीं हुए हैं, तो कहीं मोटर पंप लगा नहीं है। हरिभूमि ने गुरुवार को जिले के ऐसे कई ग्रामों में जल जीवन मिशन अंतर्गत किए गए कार्यों की पड़ताल की। इस पड़ताल में खुलासा हुआ है कि जल जीवन मिशन का कार्य सिर्फ मिशन के रूप में चल रहा है, जबकि इस योजना से जल गायब है। यही कारण है कि कई वर्षों पहले योजना का कार्य शुरू होने के बाद भी इस भीषण गर्मी में कई गांववासियों को जल की समस्या से जूझना पड़ रहा है।

जल जीवन मिशन से जल गायब मिशन जारी

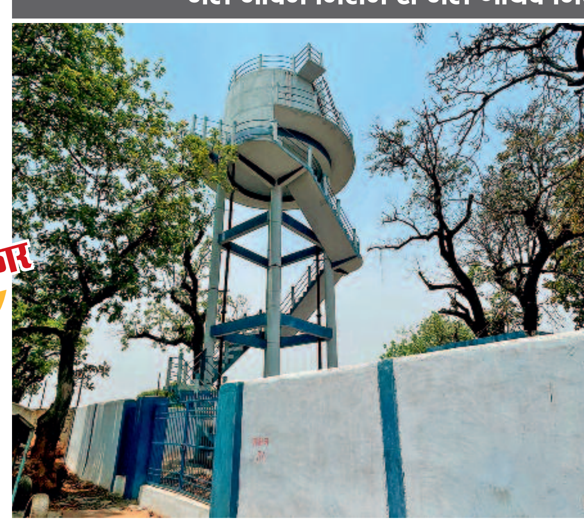

केस 1

कविता हेमंत कश्यप जिला पंचायत सदस्य ने बताया कि उसके ग्राम पंचायत में टंकी का निर्माण, पाइप लाइन बिछा दी गई है, लेकिन अभी तक टंकी से पाइप लाइन कनेक्शन जोड़ा नहीं है। उसने बताया कि गांव में पिछले 5 वर्ष से जल जीवन मिशन योजना के तहत कार्य चल रहा है। इस दौरान एक ठेकेदार काम छोड़कर भाग चुका हैं, वहीं दूसरा ठेकेदार को कार्य पूर्ण करने का ठेका दिया है।

केस 2

भीनू सुजीत घिदौड़े सदस्य जिला पंचायत रायपुर ने बताया कि उनके क्षेत्र में ग्राम छतौना मंदिर हसौद में जल जीवन मिशन के तहत कार्य तो किया गया है, लेकिन जल स्तर इतना नीचे चला गया हैं कि टंकी में पानी ही चढ़ नहीं पाता है। इसके कारण गांव में पानी टैंकर मंगाने पड़ते हैं।

केस 3

ग्राम बंजारी नवा रायपुर की सरपंच ने बताया कि उनके गांव में पानी टंकी, पाइप लाइन बिछाने का कार्य पूर्ण हो चुका हैं, लेकिन बोर सूखे डेढ़ से दो साल हो चुके है। उन्होंने बताया कि दूसरी बार नई जगह पर बोर कराया है। इसके लिए पाइन लाइन भी बिछाई गई, लेकिन जिस जगह पर नया बोर एवं पाइप लाइन बिछाई गई उसी जगह पर पीडब्ल्यूडी सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, जिसके कारण पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। इस वजह से पानी टंकी कनेक्शन से लोगों के घरों में अब तक पानी पहुंच नहीं पाया है।

केस 4

सेजबहार में पानी टंकी से लेकर पाइप लाइन बिछा दी गई है, लेकिन पानी का जल स्तर इतना डाउन है कि घरों में नल कनेक्शन के माध्यम पानी पहुंच नहीं पा रहा है। इसके कारण इस गांव में अभी भी पानी की समस्या बनी हुई है।

केस 5

खरोरा तहसील अंतर्गत ग्राम फरहदा के सरपंच संजय साहू ने बताया कि में जल जीवन मिशन अंतर्गत कार्य हुआ है, लेकिन इसके माध्यम से लोगों को पानी बहुत कम मिल पा रहा है। इसके कारण प्राइवेट बोर कराकर पानी की समस्या को दूर किया जा रहा है।

तीन माह के चावल वितरण में सारंगढ़-बिलाईगढ़ सबसे आगे, रायपुर 11वें नंबर पर

हरिभूमि न्यूजः रायपुर।

चावल उत्सव के तहत तीन माह का एक साथ चावल वितरण में सारंगढ़-बिलाईगढ़ सबसे आगे है। इस जिले में कुल 69.52 प्रतिशत चावल का वितरण हो चुका है। दूसरे नंबर पर बलौदाबाजार 68.36 प्रतिशत तथा तीसरे नंबर पर बिलासपुर है, जहां 67.52 प्रतिशत वितरण हुआ है। रायपुर जिला वितरण में 11वें नंबर पर है। जिले में 60.62 प्रतिशत चावल वितरण हुआ है। सबसे कम सुकमा, बीजापुर, राजनांदगांव, कवर्धा, कांकेर एवं दंतेवाड़ा में हुआ है, जहां वितरण का प्रतिशत 40 प्रतिशत से भी कम है।

चुनौती साबित हो रहा तीन माह का चावल वितरण

शासन ने चावल उत्सव के रूप में जरूर हितग्राहियों को सुविधा देने के लिए तीन माह का चावल एक साथ वितरण करने का आदेश जारी किया है, लेकिन यह आदेश खाद्य, नागरिक एवं आपूर्ति विभाग के चुनौती साबित हो रहा है। तीन माह का चावल का स्टॉक राशन दुकानों में करने के लिए कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, जिसके कारण दुकानदारों से लेकर हितग्राहियों को भी परेशान होना पड़ रहा है। दुकानों में स्टॉक की कमी के कारण कई जिलों में वितरण धीमी गति से हो रहा है, वहीं कुछ जिलों में वितरण का प्रतिशत अच्छा भी है।

तीन माह का चावल वितरण का प्रतिशत जिलेवार

जिला	प्रतिशत
सारंगढ़-बिलाईगढ़	69.52
बलौदाबाजार	68.36
बिलासपुर	67.52
मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	67.19
जांजगीर	66.40
मुंगेली	65.86
धमतरी	65.81
बालोद	62.56
सक्ती	62.41
नारायणपुर	60.81
रायपुर	60.62
रायगढ़	60.49
दुर्ग	56.95
मोहला-मानपुर-अंबागढ़चौकी	56.50
बलरामपुर	56.41
महासमुंद	55.58
बेमेतरा	55.23
गरियाबंद	55.04
कोरबा	50.36
खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	49.26
सूरजपुर	49.19
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही	48.56
कोंडागांव	47.11
बस्तर	43.63
सरगुजा	42.47
जशपुर	40.93
दंतेवाड़ा	38.79
कांकेर	38.54
कवर्धा	37.98
राजनांदगांव	35.37
बीजापुर	34.23
सुकमा	30.46

चैंबर ने मुख्य आयकर आयुक्त को सौंपे महत्वपूर्ण सुझाव

हरिभूमि न्यूज ▶▶| रायपुर

छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष सतीश थौरानी के मार्गदर्शन में गुरुवार को चैंबर प्रतिनिधिमंडल, केंद्रीय राजस्व भवन, सिविल लाइंस स्थित मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय में आयोजित बैठक में शामिल हुआ।

इस अवसर पर चैंबर के कार्यकारी अध्यक्ष राधा किशन सुन्दरानी लोकसभा सांसद रूप कुमारी चौधरी के उपस्थिति में के. देवरत्न कुमार मुख्य आयकर आयुक्त एवं ऋतुपर्ण नामदेव अतिरिक्त आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर प्रदेश के व्यापारिक संगठनों की ओर से आयकर प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाने अहम सुझाव दिए। राधाकिशन सुन्दरानी ने बैठक में इस बात पर जोर दिया कि विभाग और करदाताओं के बीच प्रवर्तन से अधिक सुविधा की नीति अपनाई जानी चाहिए। व्यापारिक संगठनों के बीच नियमित संवाद के लिए एक तंत्र विकसित किया जाए और आरडीटीएसीकी बैठकों को त्रैमासिक आधार पर आयोजित किया जाए। इसी तरह नोटिस की जटिलता को कम करने और छोटे व मध्यम करदाताओं के लिए 'सिम्प्लीफाइड कम्प्लायंस फ्रेमवर्क' लागू करने की मांग की गई। चैंबर के प्रतिनिधि मंडल ने केवल रिस्क-आधारित स्क्रूटनी को ही प्राथमिकता देने का सुझाव दिया।

सरकारी कर्मचारी भी राजनीतिक गतिविधियों में हो सकते हैं शामिल, रोक का आदेश वापस

अपने ही आदेश पर 24 घंटे के भीतर यू-टर्न ले लिया

हरिभूमि न्यूज ▶▶| रायपुर

छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। छत्तीसगढ़ शासन ने सरकारी कर्मचारियों पर राजनीतिक और अन्य संगठनों में शामिल होने की रोक संबंधी आदेश को अब वापस ले लिया है।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 21 अप्रैल को जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सरकारी कर्मचारी किसी भी राजनीतिक दल या संगठन की गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकेंगे। साथ ही अधिकारी की बिना अनुमति के किसी भी संस्था, समिति या संगठन में पद धारण करने पर भी रोक लगाई गई थी। आदेश के अनुसार, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियमों के तहत सभी शासकीय सेवकों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन निष्पक्षता, ईमानदारी और निष्ठा के साथ करना अनिवार्य है। इसी के तहत उन्हें किसी भी राजनीतिक दल या संगठन का सक्रिय सदस्य बनने से प्रतिबंधित किया गया है।

सिर्फ 24 घंटे में रद्द हुआ आदेश

छत्तीसगढ़ शासन ने शासकीय कर्मचारियों के राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने को लेकर जारी अपने ही आदेश पर 24 घंटे के भीतर यू-टर्न ले लिया और आदेश को वापस ले लिया। नए आदेश में स्पष्ट किया गया कि 21 अप्रैल वाला निर्देश आगामी आदेश तक स्थगित रहेगा। उप सचिव अंशिका पांडेय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 21 अप्रैल के आदेश के निर्देश फिलहाल प्रभावी नहीं रहेंगे, जिससे अब इन नियमों पर कार्रवाई पर भी अगले आदेश तक रोक लगा दी है।

फेडरेशन के विरोध के कारण वापस लेना पड़ा

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने बताया, कल इस आदेश का विरोध सचिव सामान्य प्रशासन विभाग एवं उप सचिव अंशिका पांडेय से व्हाट्सएप के माध्यम से किया था। भविष्य में इस आदेश का विरोध हर स्तर पर करने का लेख किया था। फेडरेशन के विरोध के चलते राज्य शासन को उक्त आदेश को वापस लेना पड़ा।

जीएडी के जिम्मेदार अधिकारी हटाए जाएं- नामदेव

राष्ट्रवादी संगठन भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने इस पूरे घटनाक्रम पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा, जब सिविल सेवा (आचरण) नियम पहले से स्पष्ट और प्रभावी हैं, तब नया आदेश जारी करने की आवश्यकता ही क्या थी। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि आदेश इतना ही त्रुटिपूर्ण था कि 24 घंटे के भीतर उसे निरस्त करना पड़ा, तो आखिर ऐसा आदेश जारी ही क्यों किया गया? यह पूरा मामला अब कई सवालों के घेरे में है।

आरएसएस के दबाव में आदेश पर रोक लगाई गईः कांग्रेस

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, सरकार का बेहद आश्चर्यचकित करने वाला आदेश आया है, पहले सरकार ने 21 अप्रैल को आदेश निकाला था कि शासकीय कर्मचारियों को किसी भी राजनैतिक दल एवं सामाजिक संगठन में भाग लेने पर प्रतिबंध है। उसके बाद 22 अप्रैल को आदेश आया कि 21 अप्रैल का आदेश था, उसमें आगामी आदेश तक रोक लगायी जाती है। नये आदेश के बाद आज की तारीख में छत्तीसगढ़ में कोई भी कर्मचारी राजनैतिक दल का सदस्य बन सकता है, सामाजिक संगठन का सदस्य बन सकता है। आदेश से पता चलता है कि या तो सरकार अफीम खाकर चल रही या फिर अनाड़ी लोगों के दबाव में चल रही है। प्रदेश कांग्रेस ने कहा, सरकार ने 21 अप्रैल के आदेश को क्यों निकाला था, जबकि यह तो स्थापित नियम है शासकीय कर्मचारी अपनी सर्विस रूल के अनुसार किसी भी राजनीतिक एवं गैर राजनीतिक संगठन के कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो सकता।

खरीफ सीजन के लिए बीज निगम ने जारी किया परिपत्र

अनाज, दलहन-तिलहन के प्रमाणित बीजों की विक्रय दर निर्धारित

हरिभूमि न्यूज ▶▶| रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड द्वारा चालू खरीफ सीजन के लिए अनाज, दलहन एवं तिलहन फसलों के प्रमाणित एवं आधार बीजों के विक्रय दर निर्धारित कर दिए गए हैं। इस संबंध में राज्य स्तरीय बीज विक्रय दर निर्धारण समिति की बैठक में विभिन्न फसलों के बीजों की दरों को अनुमोदित किया गया।

राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार धान (मोटा एवं पतला), धान सुगंधित, कोदो-कुटकी, रागी, उड़द, मूंग, कुल्थी, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, रामतिल, ज्वार तथा अरहर सहित प्रमुख फसलों के लिए अलग-अलग अवधि एवं किस्मों के आधार पर दरें तय की गई हैं। धान मोटा की दर 3,478 रुपये प्रति क्विंटल तथा धान पतला की दर 3,919 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की गयी है। वहीं तिल के बीजों की कीमत 20,539 रुपये प्रति क्विंटल तक रखी गई है, जो उच्च श्रेणी में शामिल है।

इस प्रकार होंगी दरें

इसी प्रकार सभी किस्मों के सुगंधित धान कृषकों के लिए 4803 रुपए प्रति क्विंटल तथा सहकारी समितियों के लिए 4611 रुपए निर्धारित की गई है। कोदो-कुटकी की दरें कृषकों के लिए 7245 तथा समितियों के लिए 6995 रुपए, रागी किस्मों के लिए 7229 रुपए तथा समितियों के लिए 6940 रुपए, उड़द 5 वर्ष के अंदर के किस्में किसानों के लिए 14351 तथा समिति के लिए 13777 रुपए, उड़द 10 वर्ष के अंदर के किस्मे किसानों के लिए 1407 तथा समिति के लिए 13777 रुपए, उड़द 10 वर्ष के ऊपर के किस्मे 14351 तथा समिति के लिए 13777 रुपए प्रति क्विंटल की दर तय की गई है।

सोयाबीन किसानों के लिए 9573 तथा समिति के लिए 9190 रुपए, सोयाबिन 10 वर्ष के ऊपर के किस्मे किसानों के लिए 9805 तथा समिति के लिए 13413 रूपए निर्धारित की गई है। मूंगफली 10 वर्ष के अंदर के किस्मे किसानों के लिए 11816 तथा समिति के लिए 11343 रुपए, मूंगफली 10 वर्ष के ऊपर के किस्मे किसानों के लिए 11816 तथा समिति के लिए 11343 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है। इसी तरह अरहर 10 वर्ष के अंदर के किस्मे किसानों के लिए 11369 तथा समिति के लिए 10914 रुपए, अरहर 10 वर्ष के ऊपर के किस्मे किसानों के लिए 13220 तथा समिति के लिए 12651 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है। वहीं रामतिल की समस्त किस्में किसानों के लिए 12846 रुपए तथा समितियों के लिए 12332 रुपए तथा ढेंचा के सभी किस्में किसानों के लिए 22057 तथा समितियों के लिए 21175 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है।

निर्धारित दरों पर किसानों को वितरण

बीज निगम के अनुसार सहकारी समितियों को देयक जारी करते समय निर्धारित दरों पर 4 प्रतिशत कमीशन की कटौती की जाएगी। साथ ही आधार बीजों की विक्रय दर, प्रमाणित बीजों की दर से 100 रुपये प्रति क्विंटल अधिक होगी। परिपत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि भारत सरकार एवं राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उत्पादन एवं वितरण अनुदान को समायोजित करते हुए बीजों की अंतिम विक्रय दर तय की गई है। खरीफ के लिए किसानों को बीज वितरण निर्धारित दरों के अनुसार किया जाएगा।

निगम द्वारा उत्पादित बीजों पर अनुदान

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन तथा अन्य केंद्रीय योजनाओं के तहत बीज वितरण में नियमानुसार अनुदान की राशि जोड़कर अथवा घटाकर दरें लागू की जाएंगी। उत्पादन अनुदान केवल निगम द्वारा उत्पादित बीजों पर ही देय होगा। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को देय भुगतान नियमानुसार कमीशन राशि घटाकर किया जाएगा। इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों एवं संस्थाओं को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

विश्व रेडक्रॉस दिवस पर होंगे राज्य स्तरीय कार्यक्रम

रायपुर। विश्व रेडक्रॉस दिवस 8 मई के अवसर पर छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में रेडक्रॉस राज्य शाखा रायपुर के चेयरमैन तोमन साहू की अध्यक्षता में कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रॉस भवन में बैठक रखी गई, जिसमें विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर सूची जारी की गई। निर्धारित कार्यक्रमों के तहत समूह नृत्य, प्रहसन एवं चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें प्रदेशभर के रेडक्रॉस वालिंटियर्स भाग लेंगे। प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। बैठक में रेडक्रॉस गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाने पर विशेष जोर दिया गया। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हेतु जन-जागरूकता अभियान, प्राथमिक उपचार (फर्स्ट एड) प्रशिक्षण का विस्तार तथा विशेष अवसरों पर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन शामिल है। साथ ही रक्तदान शिविरों को वृहद स्तर पर आयोजित कर जरूरतमंदों के लिए रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। जूनियर रेडक्रॉस एवं यूथ रेडक्रॉस सोसायटी के माध्यम से विद्यार्थियों को मानवीय सेवा से जोड़ने और उनमें सेवा भाव विकसित करने पर भी बल दिया गया।

खबर संक्षेप

निःशुल्क कैंसर जांच एवं परामर्श शिविर आज

मगरलोड। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करेली बड़ी में 25 अप्रैल को सुबह 10 बजे से निःशुल्क कैंसर जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर गैर संचारी रोग प्रकोष्ठ जिला अस्पताल धमतरी, जिला स्वास्थ्य समिति और जगतती फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जाएगा। शिविर में मुंह का कैंसर, स्तन कैंसर, बच्चादानी का कैंसर और फेफड़े का कैंसर की निःशुल्क जांच और परामर्श दी जाएगा। जांच के दौरान आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा, जिनमें प्रमुख रूप से मोनोग्राफी, पैप स्मीयर, ब्रश साइटोलॉजी शामिल है।

ऑनलाइन आवेदन 8 मई तक

धमतरी। एकीकृत बाल विकास परियोजना परियोजना मगरलोड के तहत आंगनबाड़ी केन्द्र चारभाठा (कोरगांव) में आंगनबाड़ी सहायिका की भर्ती के लिए ऑनलादन आवेदन 8 मई तक आमंत्रित किए गए हैं। परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना मगरलोड ने बताया कि उसी ग्राम की निवासरत इच्छुक पात्र महिलाएं निर्धारित तिथि तक आवेदन कर सकती हैं।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रवेश शुरू

मगरलोड। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय भैंसमुण्डी (मगरलोड) में शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। विद्यालय में कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रवेश के लिए विशेष रूप से उन बालिकाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जो शाला त्यागी हैं, अनाथ हैं, एकल अभिभावक के संरक्षण में रह रही हैं, दूरस्थ अंचलों से आती हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित हैं या पलायन के कारण शिक्षा से वंचित रही हैं। पात्र बालिकाओं को उनकी आयु के अनुसार उपयुक्त कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा।

कर्मचारियों से ओवरटाइम ड्यूटी अनियमितता पर नोटिस जारी

जिला स्तरीय गठित संयुक्त टीम ने किया बिरकोनी औद्योगिक क्षेत्र का निरीक्षण

हरिभूमि न्यूज ▶▶| महासमुंद

जिला स्तरीय गठित संयुक्त टीम द्वारा मनोरमा इंडस्ट्रीज लिमिटेड परसवानी रोड बिरकोनी इंडस्ट्रियल एरिया का निरीक्षण किया गया। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के आदेश के परिपालन में निरीक्षण के दौरान रामकुमार ध्रुव जिला परिवहन अधिकारी, दिनेश कंवर प्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, डीएन पात्र श्रम पदाधिकारी श्रम विभाग, नीलिमा सोनकर मुख्य रसायनज्ञ पर्यावरण विभाग, सिद्धार्थ दुबे निरीक्षक विधिक माप विज्ञान विभाग, बेलारसन बघेल श्रम उप निरीक्षक श्रम विभाग उपस्थित रहे।

निरीक्षण के दौरान परिवहन विभाग की जांच में कोई अनियमितता नहीं पाई। उद्योग विभाग की जांच में कोई अनियमितता नहीं पाई गई। पर्यावरण विभाग की जांच में प्लांट सुचारू रूप से संचालित पाया गया। निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई। विधिक माप विज्ञान विभाग की जांच में माप तौल संबंधित प्रक्रिया सही व तौल यंत्र सत्यापित पाए गए, सामान्य निर्देशों का पालन करना पाया गया। श्रम विभाग द्वारा संविदा श्रमिक अधिनियम, 1970, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, वेतन भुगतान अधिनियम 1936, के अंतर्गत जांच / निरीक्षण किया गया। फैक्ट्री रोल में कुल 262 कर्मचारी स्थानीय निवासी नियोजित पाए गए एवं 148 अति उच्च कुशल कर्मचारी अन्य प्रदेश के निवासी नियोजित पाए गए तथा ठेकेदारों के नियोजन 222 कर्मचारी कार्यरत पाए गए जो कि स्थानीय निवासी है। जांच में कर्मचारियों से संबंधित रिकार्ड संधारित होना बताया गया।

समक्ष में प्रस्तुत नहीं किया गया। ठेकेदारों द्वारा ओवर टाइम लिया जाना पाया गया। ओवर टाइम से संबंधित रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया। सूचना बोर्ड प्रदर्शित पाया गया। परंतु वांछित जानकारी का प्रदर्शन नहीं पाया गया। इस संबंध में प्रबंधन एवं ठेकेदारों को नोटिस जारी किया जा रहा है। आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जाना पाया गया।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन को लेकर बीजेपी का विपक्ष पर तीखा हमला

महासमुंद। नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को जिला भाजपा कार्यालय में प्रेसवार्ता आयोजित की। इस दौरान बीजेपी के नेताओं ने अधिनियम को महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। प्रेसवार्ता में प्रदेश प्रवक्ता किरण बघेल, विधायक पुरंदर मिश्रा, जिलाध्यक्ष येतराम साहू सहित भाजपा के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता किरण बघेल ने कहा कि देश की आधी आबादी को नीति निर्धारण की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी दिलाने के उद्देश्य से नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वार्थी विपक्ष ने पिछले 30 वर्षों तक महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण में बाधा उत्पन्न की और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने में देरी की। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने एक बार फिर देश की महिलाओं को निराश किया है और उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को कमजोर करने का काम किया है। साथ ही यह भी आरोप लगाया कि विपक्ष के रुख से उच्च पदों पर आसीन महिलाओं के प्रति उनका नजरिया उजागर होता है। किरण बघेल ने कहा कि वर्ष 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद महिलाओं के उत्थान, अधिकार और सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं। भाजपा माताओं, बहनों और बेटियों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

छात्रावास में छात्रों का शिक्षा, अनुशासन और करियर मार्गदर्शन से संवर रहा है भविष्य

हरिभूमि न्यूज ▶▶| महासमुंद

जिले के बागबाहरा में स्थित अनुसूचित जाति बालक प्री-मैट्रिक छात्रावास आज मेहनत, अनुशासन

और सही मार्गदर्शन के बदौलत सफलता की नई पहचान बना रहा है। यहां के छात्र सीमित संसाधनों के बीच भी बड़े सपने देख रहे हैं और उन्हें साकार करने में जुटे हैं। छात्रावास अधीक्षक मनोज चौधरी के मार्गदर्शन में यहां पढ़ाई का स्तर लगातार बेहतर हुआ है। इसी का परिणाम है कि इस वर्ष यहां के 7 छात्रों का चयन प्रतिष्ठित प्रयास आवासीय विद्यालय के लिए हुआ है। एक ही छात्रावास से इतने छात्रों का चयन होना एक बड़ी उपलब्धि है और यह यहां की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को दर्शाता है। यह छात्रावास पढ़ाई के साथ छात्रों के कैरियर निर्माण में भी भूमिका निभा रहा है। यहां के एक छात्र कड़ी मेहनत के बल पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में चयन होकर छात्रावास का नाम रोशन किया है। उसकी सफलता अन्य छात्रों के लिए प्रेरणा बन गई है। शैक्षणिक क्षेत्र में भी छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। कक्षा दसवीं की बोर्ड परीक्षा में यहां के दो छात्रों ने अपने विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए छात्रावास में डिजिटल बोर्ड के माध्यम से स्मार्ट लर्निंग की सुविधा दी जा रही है, जिससे छात्र आधुनिक तरीके से तैयारी कर रहे हैं। छात्रावास का वातावरण भी बेहद सकारात्मक और घर जैसा है। यहां छात्रों के शारीरिक विकास के लिए ओपन जिम की सुविधा उपलब्ध है।

जिले में ई-ऑफिस से फाइल ट्रैकिंग आसान काम में तेजी और जवाबदेही भी सुनिश्चित

हरिभूमि न्यूज ▶▶| महासमुंद

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिजिटल इंडिया पहल और विष्णुदेव साय के सुशासन एवं पारदर्शिता के संकल्प को साकार करते हुए महासमुंद जिला प्रशासन ने ई-ऑफिस प्रणाली को तेजी से अपनाया है। शासन की प्राथमिकता के अनुरूप ई-ऑफिस प्रणाली अब जिले के लगभग सभी विभागों में गति पकड़ चुकी है।

जिले के लगभग सभी विभागों में अब परंपरागत कागज़ी फाइलों के स्थान पर ई-ऑफिस के माध्यम से कार्य किए जा रहे हैं। 1366 अधिकारी-कर्मचारियों का ई-ऑफिस के लिए ऑनबोर्डिंग किया जा चुका है, जो इस प्रणाली के व्यापक क्रियान्वयन को दर्शाता है। अब तक लगभग साढ़े 5 हजार से अधिक फाइलों का मूवमेंट डिजिटल माध्यम से किया जा चुका है, जिससे कार्यों में गति और दक्षता आई है।

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के मार्गदर्शन में कलेक्ट्रेट का अधिकांश कार्य ई-ऑफिस प्रणाली से संचालित हो रहा है। प्रत्येक सप्ताह समय-सीमा की बैठकों में इसकी समीक्षा कर विभागवार प्रगति की समरी रिपोर्ट ली जाती है। सभी शासकीय पत्राचार, नियमित फाइलें और वित्तीय स्वीकृतियां यहां तक कि छोटी नोटशीट्स भी अब ऑनलाइन दर्ज की जा रही हैं, जिससे कार्यों की पारदर्शिता और निगरानी आसान हो गई है। ई-ऑफिस प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण लाभ इसकी ऑनलाइन ट्रैकिंग सुविधा है। अब किसी भी फाइल की स्थिति को आसानी से देखा जा सकता है, वह किस अधिकारी के पास लंबित है और कितने समय से। इससे कार्यों में अनावश्यक विलंब कम हुआ है और जवाबदेही भी सुनिश्चित हुई है। इस प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए अधिकारी-कर्मचारियों को तीन चरणों में प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे वे फाइल निर्माण, नोटशीट लेखन और दस्तावेज अपलोडिंग में दक्ष हो चुके हैं। तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए एनआईसी और तकनीकी टीम का सहयोग भी लगातार लिया जा रहा है।

शासन की मंशा है कि भविष्य में संपूर्ण पत्राचार केवल ई-ऑफिस के माध्यम से ही किया जाए। शासन की यह कदम समय की बचत और विभागों के बीच बेहतर समन्वय तथा कार्यों में पारदर्शिता भी सुनिश्चित करेगा। महासमुंद जिले में यह पहल निश्चित रूप से डिजिटल, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन की दिशा में सार्थक रूप से संचालित हो रहा है।

खनिज विभाग ने किया जिले के विभिन्न फर्शी पत्थर खदानों का निरीक्षण

हरिभूमि न्यूज ▶▶| महासमुंद

कलेक्टर विनय लंगेह के निर्देशन में खनिज विभाग द्वारा जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में खनिज अमले द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित फर्शी पत्थर खदानों का निरीक्षण किया जा रहा तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान सभी पट्टेदारों को खदानों की निर्धारित सीमा को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के लिए सीमा स्तंभों के संधारण के निर्देश दिए गए। साथ ही प्रत्येक खदान में ग्राम, रकबा, खसरा एवं पट्टा अवधि की जानकारी दर्शाने वाली नाम पट्टिका अनिवार्य रूप से स्थापित करने को कहा गया। खदान क्षेत्रों में श्रमिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक उपचार, पेयजल एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। खनिजों के परिवहन को पारदर्शी एवं नियंत्रित बनाने के लिए शासन के निर्देशानुसार ई-टीपी के माध्यम से परिवहन सुनिश्चित करने तथा संबंधित अभिलेखों का नियमित संधारण करने भी कहा गया है। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिले में इस प्रकार की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए खनिज विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाकर निरंतर जांच और निगरानी किया जाएगा।

जिले के 1106 आंगनबाड़ी केंद्रों में पानी की उपलब्धता एवं आरओ चालू स्थिति में

हरिभूमि न्यूज ▶▶| महासमुंद

महासमुंद जिला अंतर्गत जिला खनिज न्यास संस्थान से वित्तीय वर्ष 2025-26 में 320 आरओ फिल्टर महासमुंद ब्लॉक में लगाया गया है। जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 282 एवं नगरीय क्षेत्र में 38 आंगनबाड़ी केंद्र सम्मिलित है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास टिक्वेंद्र जटवार ने वर्तमान स्थिति से अवगत कराते हुए बताया कि ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत स्थापित 282 केंद्रों में से 201 केंद्रों में पानी की पर्याप्त व्यवस्था है एवं आरओ चालू स्थिति में है, शेष 81 आंगनबाड़ी केंद्रों में 38 केंद्रों में गर्मी के कारण जलस्तर में कमी से पानी की उपलब्धता नहीं होने पर, 14 केंद्रों में रनिंग वाटर उपलब्ध नहीं होने पर, 29 केंद्रों में आरओ अन्य केंद्रों में स्थानांतरित की जा रही है। शहरी क्षेत्र के 38 केंद्रों में से 27 आंगनबाड़ी भवनों में नगर पालिका परिषद महासमुंद द्वारा मरम्मत एवं जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है। जिससे उक्त केंद्रों के आरओ फिल्टर चालू स्थिति में नहीं है। शेष 11 आंगनबाड़ी केंद्रों में आरओ स्थापित एवं चालू स्थिति में है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी जटवार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में सक्षम आंगनबाड़ी के तहत जिले के 600 आंगनबाड़ी केंद्रों में संचालनालय महिला एवं बाल विकास के माध्यम से वाटर फिल्टर प्रदाय प्रदाय किया गया है, जिसमें बागबाहरा 263, पिथौरा 112, बसना 112, सरायपाली 113 स्थापित किया गया है। सभी सक्षम 600 आंगनबाड़ी केंद्रों में आरओ चालू स्थिति में एवं पेयजल उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में जिला खनिज न्यास संस्थान से 320 आंगनबाड़ी केंद्रों में आरो फिल्टर स्थापित करने हेतु स्वीकृति प्रदान किया गया है। उक्त के तहत पिथौरा ग्रामीण क्षेत्र में 152, बसना ग्रामीण क्षेत्र में 104 आरओ स्थापित किया गया है। जिसमें सभी 284 में पेयजल व्यवस्था उपलब्ध है, शेष 36 आरओ स्थापित किया जा रहा है। इस प्रकार जिले के 1793 के विरूद्ध 1240 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए जिला खनिज न्यास निधि/सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र के लिए आरओ स्थापित करने की स्वीकृति प्राप्त है। जिसमें से 1204 आंगनबाड़ी केंद्रों में स्थापित किया जा चुका है। स्थापित 1204 आंगनबाड़ी केंद्रों में 1106 आंगनबाड़ी केंद्रों में पानी उपलब्धता एवं आरओ चालू स्थिति में है।

कंडेल में ग्रामीणों को पानी की समस्या से मिली राहत

धमतरी। कंडेल के ग्रामवासियों ने पानी की समस्या से जिला पंचायत सदस्य श्रीमती धनेश्वरी साहू को अवगत कराया था जिसे गंभीरता से लेते हुए जिला पंचायत सदस्य द्वारा 15 वें वित्त की राशि से पानी टैंकर प्रदान किया गया। लोकार्पण कार्यक्रम के अतिथि श्रीमती रंजना साहू भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में प्रतिनिधि के रूप में डीपेंद्र साहू शामिल हुए। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य श्रीमती धनेश्वरी साहू, जनपद सदस्य दिलीप सेन, सरपंच गिरधर सार्वा सहित पंचायत प्रतिनिधि एवं ग्रामवासी उपस्थित थे।

न्यायालय नायब तहसीलदार बागबाहरा, जिला-महासमुंद (छ.ग.)

// सूचना पत्र//

क्रमांक/562/तह./ वाचक / 2026

बागबाहरा, दिनांक 17/04/2026

राजस्व मामला क्रमांक 202508122000003 अ/5 वर्ष 2024-25

ग्राम-सम्हर, प.ह.न. 11. रा.नि.म. तेन्दूकोना, तहसील बागबाहरा

बाबूलाल पिता कलीराम
जाति तेली निवासी ग्राम सम्हर, तहसील बागबाहरा
जिला महासमुन्द (छ.ग.) .... आवेदक

विरूद्ध

खेमराज नायक, पिता हीरासिंह
निवासी ग्राम सम्हर, तहसील बागबाहरा जिला महासमुन्द (छ.ग.) ....अनावेदक

आवेदक बाबूलाल पिता कलीराम जाति तेली एवं अन्य निवासी ग्राम सम्हर, तहसील बागबाहरा जिला महासमुन्द (छ.ग.) के द्वारा आवेदन पेश किया गया है कि ग्राम सम्हर प.ह.न. 11 तहसील बागबाहरा स्थित भूमि पुराना ख.न. 233, 208, 209/1, रकबा क्रमशः 0.040, 0.283, 1.336 हे. कुल रकबा 1.659 हे. आवेदकगण के पिता कलीराम के नाम पर दर्ज रहा है। बंदोबस्त उपरांत उक्त भूमि का नया ख.न. 94, 103 रकबा क्रमशः 0.05, 1.36 हे. कुल रकबा 1.41 हे. दर्ज हुआ है। उक्त भूमि के रकबा एवं नक्शा में त्रुटि होकर 0.24 हे. की कमी निर्मित हो गयी है। आवेदकगण के पिता पूर्व अभिलेख अनुसार आज दिनांक तक कास्त काबिज है। अतएव बंदोबस्त सर्वेक्षण के दौरान हुई त्रुटि को सुधारकर बंदोबस्त सर्वेक्षण के पूर्वानुसार अभिलेख सुधार किया जावे। प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अनावेदक/हितबद्ध पक्षकार खेमराज नायब पिता हीरासिंह, निवासी ग्राम सम्हर, तहसील बागबाहरा, जिला महासमुन्द (छ.ग.) को इस सूचना पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन के संबंध में इस न्यायालय में राजस्व मामला क्रमांक 202508122000003 अ/5 वर्ष 2024-25 विचाराधीन है। प्रकरण में आगामी सुनवाई तिथि 27/04/2026 को नियत है। उक्त आवेदन के संबंध में नियत पेशी तिथि को न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब दावा या उजर आपत्ति पेश कर सकते हैं। जवाब दावा या उजर आपत्ति पेश नहीं करने की स्थिति में अनावेदक/हितबद्ध पक्षकार खेमराज नायब पिता हीरासिंह, निवासी ग्राम सम्हर, तहसील बागबाहरा, जिला महासमुन्द (छ.ग.) के विरूद्ध प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 17/04/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया।

मुहर

नायब तहसीलदार
बागबाहरा

Satya TRUCKING PVT. LTD.
आवश्यकता है
बिजनेस एक्जीक्यूटीव
योग्यता - ग्रेजुएशन,
स्थान- रायपुर (1 पद), नारायणपुर (1 पद), डोंगरगढ़ (1 पद), दल्ली राजहरा (1पद)
वेतन - 15,000 + इंसेंटिव
रिटेल फायनेंस मैनेजर
योग्यता - ग्रेजुएशन, स्थान- रायपुर (1 पद)
वेतन - 15,000 + इंसेंटिव
कस्टमर केयर मैनेजर
योग्यता - ग्रेजुएशन, स्थान- रायपुर (1 पद)
वेतन - 15,000 + इंसेंटिव
इलेक्ट्रीशियन+मैकेनिक
योग्यता - आईटीआई/डिप्लोमा
स्थानः रायपुर - 15 पद, राजनांदगांव-4 पद
वेतन - 15,000 + इंसेंटिव
फ्रेशर भी आवेदन कर सकते हैं।
अपना अपडेटेड रेज्यूम भेजें
noman.sinha@teamsatya.in
या कॉल करें
7748900111, 9098750248
जी.ई. रोड, टाटीबंध, रायपुर (छ.ग.)

महिला आरक्षण बिल गिराने के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित

- नगर निगम की सामान्य सभा में बहुमत के आधार पर हुआ निर्णय
- काले कपड़े में नजर आये सत्ता पक्ष के पार्षद

हरिभूमि न्यूज ▶▶| धमतरी

लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिराने को लेकर निगम की सामान्य सभा में विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव बहुमत के साथ पारित किया गया। बैठक शुरू होने से पहले ही पक्ष-विपक्ष के बीच पोस्टर वार चला। शुक्रवार को आहूत सामान्य सभा की बैठक आधे घंटे के नाटकीय घटनाक्रम के साथ समाप्त हो गई। शुक्रवार को दोपहर 12 बजे नगर निगम स्थित महापौर के कार्यालय से महापौर रामू रोहरा के साथ भाजपा पार्षदों की टीम हाथ में तख्ती लेकर नारेबाजी करते हुए सभाकक्ष के लिए निकली। भाजपा के अधिकांश पुरूष पार्षद काली शर्ट और काले गमछे पहने हुए थे। पक्ष की कई महिला पार्षद भी काले लिबास में नजर आई। इधर सभाकक्ष के प्रवेश द्वार पर विपक्ष के पार्षदों की टीम हाथ में पोस्टर लेकर महिला सभापति का अपमान नहीं सहेंगे की आवाज बुलंद करते रहे। सभा का प्रारंभ राष्ट्रीय गान और राज्यीय गीत से हुआ। सभापति श्रीमती कौशिल्या देवांगन ने महापौर को उद्बोधन के लिए कहा। महापौर रामू रोहरा ने महिला आरक्षण, शैक्षणिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण को सुदृढ़ करने, जनजागरूकता संबंधी विचार रखते हुए नारी शक्ति वंदन योजना के बारे में जानकारी दी।

महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन का खेल

कांग्रेस पार्षद दल के नेता प्रतिपक्ष दीपक सोनकर, उपनेता विशु देवांगन, योगेश लाल, सुमन मेश्राम, उमा भागी ध्रुव, विधायक प्रतिनिधि आकाश गोलछा सामान्य सभा की बैठक में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण अधिनियम 2023 दोनों सदन में पारित हो चुका है। अब महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन कराने की बदनीयती का प्रयास प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। महिलाओं के नाम पर संविधान तोड़ने की असंवैधानिक तरीके को विपक्ष ने रोक दिया। उन्होंने कहा कि 12 साल में पहली बार मोदी सरकार का बिल गिरा है। बिल नहीं, भाजपा सरकार का विश्वास गिरा है।

पालगांव के ग्रामीणों से अतिक्रमणकारियों ने की मारपीट

हरिभूमि न्यूज ▶▶| धमतरी

वन प्रबंधन समिति एवं पालगांव के ग्रामीणों ने बोदलवंडी अतिक्रमण हटाने के मामले में बाहरी व्यक्तियों द्वारा लोगों को भड़काने की शिकायत कलेक्टर से की है।

वन प्रबंधन समिति के अध्यक्ष फकीरराम एवं ग्रामीणों ने कलेक्टर को आवेदन सौंपकर कहा है कि वन प्रबंधन समिति पालगांव एवं पालगांव के ग्रामीणों ने वन विभाग को बोदलवंडी से अतिक्रमण हटाने आवेदन दिया था। 15 अप्रैल को अतिक्रमण हटाने के लिए समिति, ग्रामवासी, वन विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे। नोटिस और समझाइश देने के बाद भी अतिक्रमण नहीं छोड़ने पर कार्रवाई की गई। समिति ने पूर्व सरपंच सहित कुछ लोगों की नामजद शिकायत कर कहा है कि इनके द्वारा अतिक्रमण को बढ़ावा दिया जा रहा है। वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। आदिवासियों के नाम पर अतिक्रमण करना और अतिक्रमणकारियों से पैसा वसूल कर अतिक्रमण को बढ़ावा दिया जा रहा है।

ब्लॉक स्तरीय बैठक में कई एजेंडों पर हुई चर्चा

धमतरी। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के ब्लॉक शाखा नगरी की ब्लॉक स्तरीय बैठक हुई। बैठक में समस्त एजेंडों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। वरिष्ठ उपप्रांताध्यक्ष एसआर टण्डन ने संगठन को मजबूत बनाने तथा संगठन के इतिहास के बारे में जानकारी दी। मनोज वाधवानी ने संगठन को सशक्त बनाने पर जोर देते हुए बताया कि छोटी-छोटी समस्याओं के समाधान से ही संगठन को मजबूती मिलती है।

HEALTH TOWN
DR. ABHIMANYU'S AYURVEDA MULTISPECIALITY HOSPITAL
PAIN | PANCHKARMA | PILES | PEDIA | GYNAE | SKIN
> वात रोग > घुटने के दर्द > पीठ व कमर दर्द > स्पॉन्डिलाइटिस > लिगामेंट के दर्द
> साइटिका > गोल्फ एल्बो > फ्रोजन शोल्डर > शरीर मे जकड़न
जोड़ों, नसों, मांसपेशियों के सभी प्रकार के दर्द का इलाज
सिटी सेन्टर - कृष्णा टॉकीज के सामने, समता कॉलोनी रायपुर (छ.ग.) 9826446666
सेक्टर -7 कमल विहार, रायपुर (छ.ग.) 95224-66664, 62622-22003
Piles Care Clinic
ISO 9001:2015 Certified Clinic
Unit of Dr Abhimanyu's Pain Relief Center
बिना चीरफाड़ के बवासीर (पाइल्स), फिस्टुला (भगंदर) फिशर्स, पिलोनिडल साइनस का
लेज़र मशीन /क्षार सूत्र द्वारा आपरेशन की सुविधा
लेडिस डॉक्टर उपलब्ध
विज्ञापन हेतु संपर्क करें : 0771-4242213, 7987119756, 9303508130

पीएम आशा के तहत दलहन-तिलहन खरीदी जारी, पंजीयन की तारीख बढ़ी

हरिभूमि न्यूज ▸▸| महासमुंद

- सरसों के लिए 30 अप्रैल तथा चना के लिए 15 मई तक पंजीयन सुविधा
- जिले में अब तक 27 कृषकों से चना 9.43 क्विंटल एवं सरसों 404.51 क्विंटल की खरीदी

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) की प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत रबी वर्ष 2025-26 में दलहन एवं तिलहन फसलों की खरीदी महासमुंद जिले में जारी है। जिले के तीन उपार्जन केंद्रों कृषि उपज मंडी बसना, सरायपाली एवं पिटियाझर में आज समर्थन मूल्य पर किसानों से उपज की खरीदी की गई।

उप संचालक कृषि एफआर कश्यप ने बताया कि कृषि उपज मंडी बसना में ग्राम बेलटिकरी के कृषक चिंतामणि पटेल द्वारा 106 क्विंटल सरसों बीज का उपार्जन किया गया। साथ ही 12 अन्य कृषकों से 232.50 क्विंटल उपज की खरीदी हुई, जिससे कुल 338.50 क्विंटल उपार्जन दर्ज किया गया। वहीं, कृषि उपज मंडी सरायपाली में 4 कृषकों से 11 क्विंटल सरसों तथा पिटियाझर केंद्र में 1 कृषक से 6 क्विंटल सरसों की खरीदी की गई।

कार्यक्रम के दौरान विभागीय अधिकारियों, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं समिति प्रबंधकों की उपस्थिति में सरसों की गुणवत्ता जांच, तौल प्रक्रिया तथा खरीदी व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। किसानों को समर्थन मूल्य पर उपज विक्रय की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए पारदर्शी एवं सुचारू खरीदी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। वर्तमान में समर्थन मूल्य चना के लिए 5875 रुपए प्रति क्विंटल, मसूर के लिए 7000 रुपए प्रति क्विंटल तथा सरसों के लिए 6200 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित है।

उपसंचालक कृषि कश्यप ने बताया कि किसानों को अधिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से ई-समृद्धि पोर्टल पर पंजीयन की अंतिम तिथि में वृद्धि की गई है। सरसों के लिए पंजीयन की तिथि 30 अप्रैल 2026 तथा चना के लिए 15 मई 2026 तक बढ़ा दी गई है। उप संचालक कृषि द्वारा जिले के सभी 6 उपार्जन केंद्रों पिटियाझर, सिर्रीपठारीमुड़ा, कोमाखान, पिथौरा, बसना एवं सरायपाली के माध्यम से अधिक से अधिक किसानों से पंजीयन कराकर योजना का लाभ लेने का आव्हान किया गया है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन किसानों की आय में वृद्धि के लिए निरंतर प्रयासरत है। जिले में अब तक 24 अप्रैल 2026 की स्थिति में कुल 27 कृषकों से चना 9.43 क्विंटल एवं सरसों 404.51 क्विंटल की खरीदी की जा चुकी है।

खबर संक्षेप

जान से मारने की धमकी, जुर्म दर्ज

महासमुंद। महिला के साथ मारपीट करने वाले उसके भाई के विरूद्ध बसना थाने में अपराध दर्ज किया गया है। वार्ड 08 ग्राम जगदीशपुर की सोफिया नंद ने पुलिस को बताया कि 16 अप्रैल की शाम करीब 5 बजे उसके घर के सामने छोटे भाई अटल नंद ने नशे में घर से निकालने की नीयत से गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध धारा 296, 351(3) बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज किया गया है।

कार में मिली अंग्रेजी शराब और बीयर, दो लोगों पर कार्रवाई

महासमुंद। कार में शराब के अवैध परिवहन के मामले में बलौदा थाने में दो लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस ने बताया कि मुखबीर से सूचना मिली थी कि ग्राम भुरसापाली रोड से एक सफेद रंग की कार में दो व्यक्ति अवैध रूप से शराब लेकर जाने वाले हैं। जहां कुछ देर बाद एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार क्र सीजी 06 एचएफ 5420 में दो व्यक्ति आए। जिन्होंने अपने नाम भोलाराम पटेल पिता लक्ष्मण पटेल (32 वर्ष) मेडरा थाना बरमकेला जिला सारंगढ-बिलाईगढ़ और सुरेंद्र चौधरी पिता घनश्याम चौधरी (38 वर्ष) खैरमाल थाना सरायपाली होना। कार में रखे सामान के संबंध संदेहियों ने प्लास्टिक थैले में 20 नग मैक्डावल नं. 01 अंग्रेजी शराब एवं एक अन्य प्लास्टिक थैले में 10 नग सिंबा बीयर कुल कीमत 5900 रुपए रखना बताया। पुलिस ने शराब जब्त कर आरोपियों के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की।

खरोरा में माता जानकी जयंती मनाई गई

महासमुंद। ग्राम खरोरा में माता जानकी जयंती मनाई गई। संवेदना समूह खरोरा के सदस्य मुकेश चंद्राकर ने कहा कि मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को सीता नवमी पड़ती है। इस दिन को माता सीता के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को जानकी जयंती भी कहा जाता है। सीता नवमी के रूप से मनाया जाता है। इस दिन विधि-विधान से माता सीता की पूजा अर्चना करते हैं।

हायर सेकंडरी स्कूल झलप और रायतुम के लिए दस-दस लाख स्वीकृत

झलप। संचालक लोक शिक्षण विभाग द्वारा शासकीय शालाओं में प्रार्थना शेड निर्माण, मरम्मत के लिए महासमुंद जिले में चार करोड़ तीन लाख आठ हजार रुपए की स्वीकृति कलेक्टर को प्राप्त हुई। जिसमें से शासकीय हायर सेकंडरी स्कूल झलप और रायतुम के लिए दस-दस लाख रुपए से प्रार्थना शेड का निर्माण के लिए ग्राम पंचायत को एजेंसी नियुक्त किया गया है। इस स्वीकृति के लिए विधायक प्रतिनिधि शम्मी सलूजा ने कहा कि विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा के अथक प्रयास से हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रार्थना शेड निर्माण की स्वीकृति मिली है, इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, वित्त मंत्री ओपी चौधरी एवं विधायक राजू सिन्हा का शम्मी सलूजा, निर्भय नायक, कुलजीत सलूजा, देवा नायक, कमल कौशिक, राकेश साहू सरपंच झलप एवं रमन ठाकुर सरपंच रायतुम ने आभार जताया है।

आयोजन : पटपरपाली पंचायत में मनाया गया राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस

सशक्त पंचायत के संकल्प को मजबूत करने पर दिया जोर

हरिभूमि न्यूज ▸▸| पटपरपाली(कोमाखान)

ग्राम पंचायत पटपरपाली में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। हर साल 24 अप्रैल को देशभर में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। यह दिन पंचायती राज संस्थाओं को सांविधानिक दर्जा देने वाले ऐतिहासिक 73वें सांविधानिक संशोधन की 33वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य मनाया जाता है।

कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता एवं छत्तीसगढ़ महतारी की पूजन अर्चना से की गईं। पंचायती राज दिवस विशेष ग्राम सभा में पटपरपाली सोसायटी अध्यक्ष कमलेश कुमार टांडेय ने अपने वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय पंचायती राज का यह दिन 24 अप्रैल 1993 को लागू हुए 73वें संवैधानिक संशोधन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जिसमें भारत में ग्रामीण स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस दिन को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य पंचायतों को जमीनी स्तर पर आत्मनिर्भर बनाने और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करना है। साथ ही उनकी भूमिका को मजबूत करना है। पटपरपाली सरपंच लता कमलेश टांडेय ने अपने संबोधन में ग्राम स्वराज, सशक्त पंचायत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत करने पर जोर दिया। इस मौके पर पंचायत सचिव बेदनाथ देवांगन ने आगामी कार्यक्रमों एवं कार्यों की जानकारी के साथ उपस्थित सभी नागरिकगणों को स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता के लिए शपथ दिलाई गई।

यह कार्यक्रम पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने और जनसेवा के प्रति जिम्मेदारी व समर्पण को सुदृढ़ करने, अंत्योदय की अवधारणा को पूरा करने, स्वच्छता को बढ़ावा देने, जल ही जीवन है को संकल्पित करने एवं जल संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। बैठक में पंच प्रमुख सुनीता साहू, हेमलता साहू, थान बाई साहू, कांति साहू, सक्रिय महिला समूह प्रमुख लखपति दीदी हेमलता साहू, प्रेमलता साहू, ऋतु साहू, वरिष्ठजनों में बिश्वा साहू, दशरथ साहू, सुरित साहू, पदुम साहू, साहू, अजय यादव आर्यन साहू आदि प्रमुख रूप से उपस्थित हुए।।

भीषण गर्मी के चलते फैसला आंगनबाड़ी केंद्रों में अब सुबह 9 बजे तक ही रहेंगे बच्चे

हरिभूमि न्यूज ▸▸| महासमुंद

भीषण गर्मी और लू के बढ़ते प्रभाव को गंभीरता से लेते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग ने बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए त्वरित और संवेदनशील निर्णय लिया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के स्पष्ट निर्देश के बाद ग्रीष्मकाल के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन समय में बदलाव करते हुए इसे 6 घंटे से घटाकर 4 घंटे कर दिया गया है। निर्देशानुसार 30 जून 2026 तक आंगनबाड़ी केंद्र प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक संचालित होंगे। वहीं 23 अप्रैल से 30 जून 2026 तक बच्चों की उपस्थिति का समय केवल सुबह 7 बजे से 9 बजे तक निर्धारित किया गया है, ताकि वे भीषण गर्मी और लू के प्रभाव से सुरक्षित रह सकें।

इस निर्धारित अवधि में बच्चों को पूर्व तय समय-सारिणी के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा के साथ-साथ पूरक पोषण आहार का नियमित वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बच्चों की शिक्षा और पोषण सेवाओं की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। आंगनबाड़ी केंद्रों में अन्य आवश्यक सेवाएं प्रातः 11 बजे तक जारी रहेंगी।

बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। गर्म हवाओं और उच्च तापमान के बीच बच्चों को सुरक्षित रूप से घर पहुंचाने की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी प्रकार की लापरवाही पर जवाबदेही तय की जाएगी। इसके साथ ही, सभी जिला अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे इन व्यवस्थाओं की सतत निगरानी करें और जिला स्तरीय समीक्षा बैठकों में इसकी प्रगति की नियमित समीक्षा करें, ताकि जमीनी स्तर पर निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।ग्रीष्मकाल समाप्त होने के बाद 01 जुलाई से आंगनबाड़ी केंद्र पुनः अपने सामान्य समय प्रातः 9:30 बजे से 3:30 बजे तक (6 घंटे) संचालित होंगे।

साल्हेभांठा में पोषण पखवाड़ा के तहत हुए विविध आयोजन

हरिभूमि न्यूज ▸▸| नर्रा

- रंगोली और प्रश्नोत्तरी, नारा लेखन प्रतियोगिता हुई

महिला एवं बाल विकास परियोजना बागबाहरा के सुपरवाजर भावना गुप्ता की उपस्थिति में पटपरपाली सेक्टर के ग्राम पंचाय साल्हेभांठा में पोषण पखवाड़ा शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरूआत मां सरस्वती व छत्तीसगढ महतारी की पूजन अर्चन कर किया। तत्पश्चात पोषण पखवाड़ा की थीम के अनुसार की गई गतिविधियों को नियमित रूप से करने के लिए पालक सत्र बैठक आयोजित की गई। सही पोषण देश रोशन की थीम पर रंगोली प्रतियोगिता और प्रश्नोत्तरी , नारा लेखन और गतिविधि पंचायतवार द्वारा प्रदर्शन की प्रतियोगिता करवाई गई। प्रतियोगिताओं के निर्णायक के रूप में पालकों ने भूमिका निभाई और शारीरिक गतिविधि कितने भई कितने में पालकों और बच्चों ने मिलकर खेल खेले। अपने बच्चों हाथ के पंजों के निशान को पहचानों का खेल भी करवाया गया। जिसमें वहां के सरपंच देव डोंगरे कार्यक्रम में उपस्थित रहे। महिला एवं बाल विभाग के सक्रिय पहलकी सराहना कर विजेताओं का पुरस्कृत कर सम्मान प्रदान किया। कार्यक्रम में सही पोषण गांव रोशन की शपथ भी ली गई।

इस दौरान सेक्टर के कार्यकर्ता संतोषी डोंगरे, शांति ठाकुर, अंजनि साहू, उषा सिन्हा, उषा चौहान, जानू साहू, डोलेश्वरी साहू, मीना साहू, लुतेश्वरी जगत, कला सोनवानी, रामेश्वरी साहू, हेमलता, तोकेश्वरी, चम्पी, गमला यादव, महेश्वरी, तेजस्वी, कौशल्या यादव, देवकुमारी आदि मौजूद रहे।

नर्रा में साप्ताहिक बाजार का शुभारंभ, ग्रामीणों में भारी उत्साह

नर्रा। ग्राम पंचायत भवन नर्रा परिसर में गुरुवार 23 अप्रैल को साप्ताहिक बाजार का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि सरपंच नामेश्वरी दीवान रही। वही विशेष अतिथि के रूप में सांसद प्रतिनिधि दुकालूराम पटेल, भाजपा नेत्री किरण यदु, पंचगण एवं ग्रामीणजन रहे। अतिथियों द्वारा विधिवत पूजा अर्चना एवं फीता काटकर शुभारंभ किया गया। बता दें कि बाजार के पहले दिन आसपास गांवों के खरीदारों और व्यापारियों की भीड़ उमड़ी रही। जहां उत्सव जैसा माहौल रहा। इस बाजार के शुरू होने से आसपास के दर्जनों गांवों के ग्रामीणों को अब ताजी हरा सब्जियां, दैनिक उपयोग की वस्तुएं और कपड़े, बर्तन उचित मूल्य पर उपलब्ध हो सकेंगे। जैसे-जैसे शाम होती गई सामान खरीदने ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। पहले दिन न केवल स्थानीय बल्कि दूर- दराज से आए व्यापारियों ने अपनी दुकानें लगाई। नर्रा में बाजार के शुरू होने से केवल व्यापार बढ़ेगा, बल्कि यह सामाजिक मेल-जोल का भी एक बड़ा केंद्र बनेगा।

आईआईटी में राष्ट्रीय अविष्कार अभियान प्रशिक्षण, शिक्षक नरेश साहू ने लिया हिस्सा

महासमुंद। राष्ट्रीय अविष्कार अभियान अंतर्गत राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ एवं आईआईटी भिलाई के समन्वय से पूर्व माध्यमिक शिक्षकों का तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण आईआईटी भिलाई में 20 से 22 अप्रैल तक रखा गया। जिसमें प्रत्येक जिले से शासकीय शिक्षकों का चयन कर प्रशिक्षण में कुल 50 शिक्षक सम्मिलित हुए। महासमुंद जिले से शासकीय बृजराज मिडिल स्कूल के विज्ञान शिक्षक नरेश साहू ने इस प्रशिक्षण में भाग लिया। यह प्रशिक्षण बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने, गतिविधि आधारित शिक्षण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रखा गया था। इस प्रशिक्षण में शिक्षकों को गणितीय सूत्र की सरल व्याख्या, दैनिक जीवन में उसका उपयोग, कम खर्च व न्यूनतम संसाधन से विज्ञान के प्रयोग करना सिखाया गया। प्रशिक्षण के दौरान आईआईटी भिलाई के रसायन, भौतिक प्रयोगशाला, मशीनरी भवनों का भ्रमण कराया गया एवं वहां होने वाले कार्य, शोध एवं प्रयोग को बताया गया। साथ ही शिक्षकों ने भी रसायन के विभिन्न प्रयोग कर देखा। स्टार गेजिंग कार्यक्रम के अंतर्गत रात्रि में दूरदर्शी से तारे व ग्रह को देखने का भी अवसर मिला। यह प्रशिक्षण बहुत ही रोचक व आनंददायी रहा, जिसका निश्चित ही बच्चों को लाभ होगा। आईआईटी में होने वाले उच्च स्तर के अध्ययन अध्यापन शोध कार्य को प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों ने निकट से जाना और अपने विद्यालय के बच्चों को इसके लिए प्रेरित करने का भी आश्वासन दिया। प्रशक्षण पश्चात प्रशिक्षण संयोजक डा. ध्रुवप्रताप सिंह व डा महबूब आलम द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।

डिजिटल जनगणना 2027, जिले में शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन

महासमुंद। भारत सरकार गृह मंत्रालय, जनगणना कार्य निदेशालय छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार भारत की डिजिटल जनगणना 2027 का कार्य दो चरणों में संपादित किया जाएगा। इसके प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य 01 मई 2026 से 30 मई 2026 तक किया जाएगा। निर्देशों के अनुरूप प्रत्येक जिले में जनगणना कार्य से संबंधित आपत्तियों एवं शिकायतों के त्वरित निवारण हेतु शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाना है। इसी क्रम में महासमुंद जिले में कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी विनय कुमार लंगेह द्वारा शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इस प्रकोष्ठ में अपर कलेक्टर सचिन भूतड़ा को अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं डिप्टी कलेक्टर (जिला जनगणना अधिकारी) मनोज कुमार खांडे, को सदस्य तथा उप संचालक (अतिरिक्त जिला जनगणना अधिकारी) मधु साहू को सदस्य नियुक्त किया गया है। कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को जनगणना कार्य को सुचारू रूप से संपादित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि आम नागरिकों की समस्याओं का समय पर समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

जिले के किसानों को एग्रीस्टैक पंजीयन कराने की अपील

महासमुंद। जिला अंतर्गत कृषकों द्वारा शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीयन अनिवार्य है। जिले के 1 लाख 67 हजार 881 कृषकों द्वारा एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीयन करा लिया गया है एवं 23 हजार 255 कृषकों का एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीयन कराना शेष है। उप संचालक कृषि एफआर कश्यप ने पंजीयन के लिए शेष कृषकों से अपील की है कि शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए कृषक अपने नजदीकी लोक सेवा केंद्र एवं सोसायटी से संपर्क कर जल्द से जल्द एग्रीस्टैक पंजीयन कराएं।